



‘ऑनलाइन ववाद समाधान’ को बढ़ावा देना

प्रिलमिस के लिये

ऑनलाइन ववाद समाधान

मेन्स के लिये:

ऑनलाइन ववाद समाधान से संबंधित तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [नीति आयोग](#) (National Institution for Transforming India- NITI Aayog) ने ‘आगामी और ओमदियार नेटवर्क इंडिया’ (Agami and Omidyar Network India) के साथ मलिकर ‘ऑनलाइन ववाद समाधान’ (Online Dispute Resolution- ODR) को आगे बढ़ाने हेतु वर्चुअल बैठक आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु:

- गौरतलब है कि वर्चुअल बैठक में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, प्रमुख सरकारी मंत्रालयों के सचिव, उद्योगजगत के अग्रणी लोग, कानून के विशेषज्ञ और प्रमुख उद्यमियों ने भाग लिया।
- इस बैठक का सामान्य वषिय भारत में ‘ऑनलाइन ववाद समाधान’ को आगे बढ़ाने के प्रयास सुनिश्चित करने के लिये सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करने की दशा में बहु-हतिधारक सहमतिकायम करना था।
- ‘ऑनलाइन ववाद समाधान’ (Online Dispute Resolution- ODR):**
 - ऑनलाइन ववाद समाधान तंत्र से तात्पर्य वैकल्पिक ववाद समाधान (Alternate Dispute Resolution- ADR) की डिजिटल तकनीक का उपयोग कर विशेष रूप से छोटे और मध्यम कस्मि के ववादों का बातचीत, बीच-बचाव और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान करना है।
 - इस वधि में ववादों के समाधान की सुवधि के लिये सभी पक्षों द्वारा ऑनलाइन प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।
 - ऑनलाइन ववाद समाधान ववादों को कुशलतापूर्वक और कफायती तरीके से सुलझाने में मददगार साबित हो सकता है।
 - ‘ऑनलाइन ववाद समाधान’ सुवधाजनक, सटीक, समय की बचत करने वाला और कफायती है।

ऑनलाइन ववाद समाधान की आवश्यकता क्यों?

- भारतीय न्यायपालिका देश में लंबित मामलों में हो रही वृद्धिकी समस्या से जूझ रही है तथा जजों की कमी से नागरिकों को भी समय पर न्याय नहीं मलि पाता है।
- इसके अतरिकित उच्चतम न्यायालय को भी सामान्य मामलों से मुक्तिकी ज़रूरत है ताकि वह अपने संवधान के आदर्शों को बनाए रखने के कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके।
- न्यायालय की प्रक्रिया आम आदमी हेतु आर्थिक दृष्टि से वहनीय नहीं होती तथा सुनवाई हेतु कई बार न्यायालय में उपस्थित होने से इनकी आजीविका भी प्रभावित होती है।

ऑनलाइन ववाद समाधान के लाभ:

- न्यायालय के लंबित मामलों में कमी आएगी।
- नागरिकों की न्याय तक सुलभ और सस्ती पहुँच सुनिश्चित होगी।
- ‘ऑनलाइन ववाद समाधान’ से मुकदमों को हल करने में तेज़ी आएगी तथा नागरिकों को त्वरित न्याय की प्राप्ति होगी।
- न्यायालयों की अवसंरचना संबंधी खर्च में कमी आएगी।
- सुवधाजनक, सटीक, समय की बचत और लागत-बचत।

ऑनलाइन वविाद समाधान के चुनौतियाँ:

- देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की पहुँच एक बड़ी समस्या है, जिसका समाधान किये बिना ऑनलाइन वविाद समाधान तंत्र के वसितार की कल्पना भी नहीं की जा सकती ।
- भारत में ऑनलाइन मध्यस्थता के कार्यान्वयन की राह में शक्तिषा की कमी और प्रौद्योगिकी तक पहुँच न होना एक और बड़ी समस्या है ।
- तकनीक का असमान वतिरण अर्थात् सभी तक तकनीक की एक जैसी पहुँच न होना भी 'ऑनलाइन वविाद समाधान' के राह की एक अन्य बड़ी बाधा है ।
- विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और ई-कॉमर्स के अवसरों का असमान वतिरण इस तंत्र की स्वीकृति और मान्यता को बाधति करता है ।

वर्तमान परदृश्य में महत्त्व:

- COVID-19 महामारी के पश्चात् नागरिकों को न्याय तक कुशल और कफियती पहुँच उपलब्ध कराने हेतु 'ऑनलाइन वविाद समाधान' के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग कयिा जा सकता है ।
- COVID-19 महामारी के दौरान ODR के माध्यम से COVID-19-संबंधी वविादों (वशेष रूप से ऋण, ऋण, संपत्ति, वाणजिय और खुदरा क्षेत्र में) का नपिटारा करना जो आर्थिक पुनरुद्धार का एक महत्त्वपूर्ण हसिा है ।

आगे की राह:

- भवषिय में न्यायपालिका के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लयि उचित उपाय कयिे जाने चाहयिे । यदरि ऐसा नहीं कयिा गया तो भारत में ऑनलाइन वविाद समाधान केवल एक सदिधांत बनकर रह जाएगा ।
- नागरिकों को सूचना एवं तकनीक से जोड़ने हेतु उन्हें प्रशक्तिषति करने के प्रयास कयिे जाने चाहयिे ।
- भवषिय एक हाइबरडि मॉडल होगा जो वास्तवकि और आभासी दुनयिा का सबसे अच्छा संयोजन होगा । हाइबरडि ससि्टम के करयिान्वयन हेतु न्याय वतिरण की पूरी प्रक्रयिा को नए सरि से तैयार करना होगा ।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/catalyzing-online-dispute-resolution-in-india>

